

आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक-08 जुलाई 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात। कुशीनगर, पीलीभीत और श्रावस्ती में नदियों का बहाव खतरे के निशान से ऊपर।
- बारिश और बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर। अधिकारियों को दिये निर्देश, भ्रमण करते हुए तेज करें राहत और बचाव कार्य।
- हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक जांच आयोग ने कई लोगों से पूछताछ कर घटना क्रम की जुटाई जानकारी।
- नीट-यूजी से सम्बन्धित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज।

राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और विभिन्न बांधों और बैराजों से नदियों में छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पीलीभीत, लखीमपुर, कुशीनगर और श्रावस्ती में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों के सम्बन्ध में पेश है आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट—

राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आम जनजीवन प्रभावित है और शहरी इलाके जलभराव से जूझ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे तराई के जिलों में शारदा, राप्ती, गंडक और घाघरा नदियों के किनारे के इलाके बढ़ से प्रभावित है। नेपाल में भारी बारिश के कारण, लखीमपुर जिले में शारदा नदी में अचानक से काफी पानी का बहाव देखा गया और कई गावों में प्रभावित इलाकों से ग्रामीणों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ा।

राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। दो बड़े बचाव अभियानों में एसडीआरएफ द्वारा श्रावस्ती और कुशीनगर जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 74 लोगों को बचाया गया। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में बारिश से जुड़े हादसों में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में और बारिश होने की भविष्यवाणी की है।

प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में रूक-रूक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने ग्यारह जुलाई तक इसी तरह बारिश होने का अनुमान जताया है। पिछले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश में अड़तालीस दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है। सबसे अधिक बारिश बस्ती में दो सौ एक दशमलव चार मिलीमीटर दर्ज की गयी। प्रदेश में एक जून से अब तक एक सौ तिरानबे दशमलव सात मिलीमीटर औसत बारिश हुयी है जो सामान्य से काफी अधिक है। लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा, रामगंगा, सरयू, गण्डक, शारदा, घाघरा और राप्ती सहित कई नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, श्रावस्ती में राप्ती, कुशीनगर में गण्डक और सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बलरामपुर जिले में लगभग बारह गांव पहाड़ी नालों के पानी से घिर गये हैं। उधर, अमरोहा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों में पानी भर गया है। उत्तराखण्ड के बनबसा बैराज से साढ़े तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यहां निचले स्थानों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच, जिलाधिकारी ने आज पीलीभीत के कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालयों को बन्द करने का आदेश दिया है।

कुशीनगर जिले की गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से खड़डा तहसील के शिवपुर गांव के चौबीस से अधिक लोगों को एनडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू कराया गया। उधर, लखीमपुर खीरी के पलियाकलां के आजादनगर गांव से बाढ़ प्रभावित पैतालीस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि बाढ़ को देखते हुए सभी संवेदनशील नदियों के तटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लट पीएससी की टीम तैनात कर दी गई है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। बाढ़ के लिये चौबीस घंटे कंट्रोल रूम संचालित किये जा रहे हैं।

राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नज़र रखें और प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करें। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को राहत राशि अविलंब प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है अथवा पशु हानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

हाथरस मामले की जांच के लिये राज्य सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग ने कल हाथरस में घटनाक्रम को लेकर कई लोगों से पूछताछ की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित इस जांच आयोग के सदस्य कल से ही हाथरस में मौजूद हैं। इस आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। छ: जुलाई को उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी जुटाई थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में जो भी वीडियो फुटेज और ऑडियो सामने आएंगे, उनको जांच में शामिल किया जायेगा। इस जांच आयोग को दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देनी है।

प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशान्त कुमार ने कल अयोध्या में सावन झूला मेला और बाइस जुलाई से प्रारम्भ हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिये शासन से पन्द्रह सौ अतिरिक्त सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

राज्य सरकार पौधरोपण जन अभियान दो हजार चौबीस के अन्तर्गत पड़ोसी देश नेपाल और सीमावर्ती राज्यों से सटे प्रदेश के जिलों में मित्र वन बसायेगी। इसके लिये पैंतीस वन प्रभागों का चयन किया गया है। सीमावर्ती जिलों में पौधरोपण कार्यक्रम के लिये वन विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिये इस साल पैंतीस करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है।

उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने बताया है कि प्रदेश सरकार पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी राज्यस्तरीय आम महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव बारह से चौदह जुलाई तक लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किया जायेगा। आम महोत्सव में प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के प्रगतिशील किसान, बागवान, उद्यान विभाग के अधिकारी और निर्यातक शामिल होंगे। इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय में नीट-यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष छब्बीस याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केन्द्र ने यह भी तर्क दिया है कि नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को आज से स्कूल की डिजिटल पंजिका में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हुए निर्धारित समय से तीस मिनट देर तक हाजिरी दर्ज कराने की सुविधा भी दी है।
